भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2880
उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2026

कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क

2880. श्री अतुल गर्ग:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान विशेष रूप से औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्रों को लक्षित उच्च गति 5जी नेटवर्क एकीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान गजियाबाद में स्पार्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए भारी उद्योगों द्वारा लाइसेंस प्राप्त या संचालित कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) का ब्यौरा क्या है;

(ग) गाजियाबाद में एमएसएमई को उनकी उत्पादन लाइनों में 5जी-सक्षम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों को अपनाने के लिए कुल कितनी केंद्रीय तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार को गाजियाबद में सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क और कैप्टिव औद्योगिक नेटवर्क के बीच स्पेक्ट्रम आवंटन विवादों या व्यतिकरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा गाजियाबाद में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए 5जी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, गाजियाबाद जिले में 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 2,527 से बढ़कर दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार 3,141 हो गई है।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान गाजियाबाद में भारी उद्योगों से दूरसंचार विभाग (डीओटी) को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के लिए वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ग) केंद्र सरकार ने 97.67 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश भर में 100 5जी लैब स्थापित की हैं जिनका उपयोग शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण और औद्योगिक आटोमेशन, खनन, ऊर्जा और ग्रिड पावर, मोटर वाहन उद्योग, मीडिया और मनोरंजन आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में 5जी यूज केस/एप्लीकेशन के विकास के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर और जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा सहित उत्तर प्रदेश राज्य में छह 5जी लैब उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, सरकार ने भारत में 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में 224 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुदान को भी अनुमोदन प्रदान किया है जो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर सहित पांच स्थानों पर उपलब्ध हैं।

गाजियाबाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) 5जी-सक्षम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) प्रोटोटाइप, कम-विलंबता एप्लीकेशन और स्मार्ट विनिर्माण सोल्यूशन की जांच के लिए निकटवर्ती 5जी टेस्ट बेड और 5जी यूज केस लैब का उपयोग कर सकते हैं।

(घ) गाजियाबाद में सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्कों और कैप्टिव औद्योगिक नेटवर्कों के बीच व्यतिकरण के संबंध में दूरसंचार विभाग को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) दूरसंचार विभाग की 100 5जी यूज केस लैब परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (एनसीए-टी), गाजियाबाद में एक 5जी यूज केस लैब स्थापित की गई है जिसका उपयोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इस लैब में निकटवर्ती इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र भी आते-जाते रहते हैं।

*****